संख्या-147/2015/754/22-4-15-119(ब)/2000टी0सी0-8(ए)

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 27 जुलाई, 2015

विषय- प्रदेश की अवशेष कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष के निर्माण हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-19673/नम-2, दिनांक-15 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्न तालिका में उल्लिखित जनपदों के कारागारों/न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों के निर्माण कराये जाने हेतु यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारापोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए रू0 1,74,10,000/-( रूपया एक करोड़ चौहत्तर लाख दस हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु कुल रू0 87,05,000/-( रूपया सत्तासी लाख पॉच हजार मात्र) के आहरण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

( धनराशि लाख रूपये में)

| क्र0 | वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष की स्थापना | स्वीकृत लागत | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | आदर्श कारागार, लखनऊ | 26.03 | 13.00 |
| 2 | नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ | 26.03 | 13.00 |
| 3 | किशोर सदन, बरेली | 26.03 | 13.00 |
| 4 | जिला कारागार, रामपुर | 26.03 | 13.00 |
| 5 | जनपद न्यायालय, रामपुर | 43.95 | 22.05 |
| 6 | जिला कारागार, आजमगढ़ | 26.03 | 13.00 |
| | योग- | 174.10 | 87.05 |

(1) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(2) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2015 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-16-प्रदेश की कारागारों एंव जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध बजट प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30 मार्च,2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-147/2015/754(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारापोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, लखनऊ, बरेली, रामपुर, आजमगढ.।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) वित्त ( व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in